Joint Committee on the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954."

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT-PUBLIC IMPORTANCE

Reported damage to cotton crop by an undiagnosed disease in Punjab, Haryana and other parts of the country.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय कृषिमंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ;

पंजाब, हरियाणा तथा देश के कुछ अन्य भागों में किसी एक अज्ञात बीमारी के कारण कपास की फसल को क्षति पहुंचने के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की और कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : Sir, no reports have been received regarding damage to cotton crops in Punjab and Haryana or other parts of the country due to any disease. However, moderate to severe incidence of cotton boll worms...

MR. SPEAKER : you say it is moderate ?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : No, Sir. I have said no reports have been received.

MR. SPEAKER : No reports have been received ?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : This is what I have said. Sir, no reports have been received regarding damage to cotton crops in Punjab and Haryana...

MR. SPEAKER : Who supplied you this report?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : The state Government.

MR. SPEAKER : The State Government has already announced certain concessions. If there were no damage, then there would have been concessions.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Sir, I am coming to that. Officially no report has been received regarding any disease. They may have announced any concessions in their States an account of damage by pests. But as far as the Central Government is concerned, because...

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : Call for the Report.

मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है, इसको पोसपोन कीजिये ।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्रसिंह) : पूरी जानकारी है जरा सुन लीजिये, जो फैक्ट्स है वह बता रहे हैं । जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को न हो तो वह मालूम नहीं है ।

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : Sir, I shall start from the beginning again.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MAHAMMED KHAN) : No reports have been received regarding damage to cotton crop in Punjab and Haryana or other parts of the country due to any disease. However, moderate to severe incidence of cotton boll worms in Khuhian Sarvar, Abohar and Fazilka blocks of Ferozepur district and Mukatsar, Malout and Lambi blocks of Faridkot district has been reported. The intensity of pest attack was more on the local varieties viz : Churar and Ganganagar than on the improved varieties which are grown in large areas. On account of the intermittent and heavy showers, the spraying schedule on

cotton in Punjab and Haryana was disrupted. Owing to heavy rains the vegetative growth was excessive which further aggravated the incidence of pests, rendering the control operations difficult. As in previous years, this year also, aerial and ground spraying operations for pest control were organised in Punjab and Haryana by the State Governments.

2. According to available information, the loss in production in Punjab is the order of 15 to 20% of the total production in the State and the damage in Haryana may be to the extent of 20 to 25%. Complete information has been called for from the States concerned on 10th of November but replies are still awaited.

For increasing cotton production in the country, there is a Centrally Sponsored Intensive Cotton Development Programme, the cost of which is shared equally by the States and the Central Governments. This programme is in operation in the States of Punjab and Haryana as well. In Punjab, this programme is in operation in four districts namely, Ferozpur, Bhatinda, Faridkot and Sangrur, and in two districts of Haryana namely, Hissar and Sirsa. Under this programme, the Central share of assistance for 1983-84 available to the two States of Punjab and Haryana was Rs. 34.44 lakhs and Rs. 28.53 lakhs respectively for various activities namely, production of breeder and fundation seeds, production of certified seeds, aerial and ground spraying, supply of plant protection equipment and demonstration. In so far as assistance under aerial and ground spraying and plant equipment is concerned the Central share released to Punjab was Rs. 14.05 lakhs and to Haryana Rs. 5.86 lakhs, for the year 1983-84. As against the target of aerial spraying of 100,000 hectares in Punjab, the coverage reported upto the end of September, 1983 was 39,000 hectares and in Haryana against the target of 30,000 hectares, the coverage reported was 24,000 hectares. Apart from this, the farmers also undertook ground spraying measures to protect their crop from the attack of pests. Normally, 4 to 6 sprays for a full season schedule of pest control are carried out. This year due to excessive and intermittent rains during whole of the season, the build up of pests was considerable and inspite of the fact that plant protection schedule was carried out, its effectiveness was reduced which has led to certain amount of damage to the cotton crops as referred to above.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हुये नुकसान के बारे में इसमें जिक्र भी नहीं किया गया है। भीलवाड़ा में 50 परसेंट और गंगानगर में 70 परसेंट नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं। यह रिपोर्ट जिस किसी की भी आई है वह विरोधाभासी है। इसमें विरोधाभास है

It is said : "No reports have been received regarding damage to cotton crop in Punjab and Haryana or other parts of the country due to any disease.

दूसरे नीचे थोड़ा, अगर होता ही नहीं तो कैसे आता? जिसने यह रिपोर्ट बनवाई है, उससे आप बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसान हैं, यह बिल्कुल गलत है कि 20 परसेंट है या 25 परसेंट है। यह बिल्कुल तबाह हो गया।

मैंने अपना हिसाब देखा, आपने 6 बार स्प्रे कराई, फिर भी असर नहीं हुआ। व्यास जी भी ठीक कहते हैं।

It needs a through investigation. This is the only cash crop on which the farmer exists.

आप देखकर कराईये। अभी उन्होंने कल पंजाब में कुछ किया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वह हमने स्टेट गवर्नमेंटस से रिपोर्ट मंगाने के बाद तैयार किया है।

MR. SPEAKER : Then that administration should be fired.

राव बीरेन्द्र सिंह : पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वहां पर पेस्ट का कितना असर हुआ है । हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई । बल्कि आपकी तरफ से पहले इत्तिला मिली कि पंजाब गवर्नमेंट को कुछ और जहाजों की जरूरत है । तो एक हैलिकाप्टर और दो बसन्त एयरक्राफ्ट पंजाब गवर्नमेंट को भेजे गये । यह तो हमने किया, किस हद तक नुकसान हुआ है, उसके बारे में 10 तारीख से हम रिपोर्ट मांग रहे हैं । अभी तक दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया है । सैंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कैसे कह दे कि कितना नुकसान हुआ है? मैं तो आपके सामने वही इनफर्मेशन दे सकता हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने यह भेजा है, उन्होंने बिल्कुल नालायकी की है ।

This is an utter negligence of their duty and they are irresponsible.

राव बीरेन्द्र सिंह : भेजा ही कुछ नहीं है । टेलीफोन पर बार-बार पूछा गया, तब अन्दाजा दिया है ।

MR. SPEAKER : This is much more than a criminal. I asked the Governor to send a team of experts to assess the damage. I do not know what has happened.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : पंजाब में राष्ट्रपति शासन है, इसलिये पंजाब के लिये केन्द्र सीधा जिम्मेदार है । मंत्री महोदय इससे कैसे बच सकते हैं?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं और अफसर भेजूंगा, जो जाकर पता करेंगे और पूरी इत्तिला लेकर आयेंगे ।

श्री रामविलास पासवान(हाजीपुर) : अगर मंत्री महोदय समाचार-पत्रों को देखें, तो उन्हें पता चल जाएगा । हम लोगों ने पेपर्ज में पढ़ा है कि 80 परसेंट फसल डैमेज हो गई है ।

MR. SPEAKER : I requested to take it personally. Don't depend on them. They should be taken to task.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि यह जो रिपोर्ट आई है, इसमें दी गई जानकारी बिल्कुल अधूरी है । इस स्टेटमेंट के पहले पैराग्राफ का पहला वाक्य यह है :

"पंजाब तथा हरियाणा अथवा देश के किसी अन्य भाग में किसी रोग से कपास की फसल की क्षति होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।"

दूसरे पैराग्राफ का पहला वाक्य इस प्रकार है :—

"उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंजाब में उत्पादन में हुई क्षति राज्य के कुल उत्पादन के 15 से 20 प्रतिशत तक है तथा हरियाणा में यह क्षति 20 से 25 प्रतिशत तक हो सकती है ।"

इन दोनों बातों में कितना बड़ा विरोधाभास है ! समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इस तरह से गुमराह करने वाली बात देश की जनता के सामने करती है? पंजाब के फिरोजपुर जिले में मुख्य रूप से नुकसान हुआ है । अगर लोक सभा के अध्यक्ष का नाम लेकर कोई बात कही जाए, तो शायद ज्यादा उचित नहीं होगा,

लेकिन मैं भारत कृषक समाज के अध्यक्ष की तरफ से दिए गए बयान और उनके द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गए पत्र का जिक्र जरूर करना चाहता हूं, जो कि अखबारों में छप चुका है। उन्होंने पत्र में कहा है कि फिरोजपुर जिले में कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ है और एक अज्ञात बीमारी से, जिसका डायग-नोसिस नहीं हो पाया है, 60 प्रतिशत कपास की फसल प्रभावित हुई है। प्रभावित फसल में कितनी क्षति हुई है, इसका सही ढंग से आकलन सरकार को करना चाहिये, ताकि किसानों को उचित सहायता दी जा सके। अखबारों में जो रिपोर्ट आई हैं, उनसे पता चलता है कि लगभग 80 फीसदी फसल के बर्बाद होने की सम्भावना है।

भारत कृषक समाज के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र में कई सवाल उठाये हैं। उनमें एक सवाल यह भी है कि किसानों ने बैंक से कर्ज लेकर के खाद और कीट-नाशक दवायें खरीदीं, जिनका उपयोग उन्होंने कपास की खेती में किया। अगर कपास की फसल बर्बाद होती है—और वह बर्बाद हो गई है—, तो किसान तबाह हो जायेंगे। इस लिए उन्हें तत्काल सहा-यता दी जानी चाहिये। वहां विशेषज्ञों की टीम भेजी जानी चाहिये, जो इस बीमारी की जांच करें और उसके निदान के उपाय सुझायें। साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिये भी सरकार को कोई गारंटी देनी चाहिये, यह भी मैं भारत कृषक समाज के अध्यक्ष की बात आपको बताना चाहता हूं।

फीरोजपुर के अन्दर कृषक कपास की फसल को काट कर पशुओं को खिला रहे हैं। अगर वह फसल बर्बाद न हुई होती या न होने की सम्भावना होती तो क्यों पशुओं को खिलाते ? यह भी खबर अखबार में छपी है।

खाद में मिलावट के कारण भी इसमें काफी नुकसान हो रहा है। फाजिल्का में 30 प्रतिशत कपास खराब हो गई जिसका मूल्य करीब 16 करोड़ रुपये है। यह खबर 9 नवम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी हुई है। कृषि मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में माननीय मंत्री जी ने भी कुछ बातें इस सम्बन्ध में कही है। उसमें उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया है कि फर्टिलाइजर्स ऐसे मिल रहे हैं जिस में मिलावट है जिसके कारण फ़सल को काफी नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि वह इस मिलावट को रोकने के लिये कुछ कारगर कार्यवाही करना चाहते हैं और उसके लिये केन्द्रीय सरकार कुछ अधिक अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ? खादों में मिलावट को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। एकोनामिक्स टाइम्स 31 अक्तूबर, 1983 का यह कहता है कि :

उर्वरकों के 22650 सैम्पल पिछले वर्ष क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशालाओं द्वारा जांच किये गये थे जिसमें 1500 सैम्पल खराब पाये गये थे और पिछले 5 वर्षों में 1 लाख 31 हजार सैम्पल का परीक्षण हुआ जिसमें 12 हजार सैम्पल खराब पाये गये थे।

तो खादों के अन्दर जो यह मिलावट हो रही है इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्य-वाही करने जा रही है इसके बारे में मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। जो मिलावट करने वाले अपराधी हैं उनको दण्डित कीजिये। यह खराब खाद अपराधियों की जानकारी में दी जा रही है। जब इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई तो अधिकारियों ने विक्रेताओं या डीलर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। तो

(श्री हरिकेश बहादुर)

ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप सख्त कार्यवाही करें जिनके बारे में बताया गया है कि सूचना मिलने पर भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं दी।

राव बीरेन्द्र सिंह : कपास के बीच में खाद कहां से आगई ?

श्री हरिकेश बहादुर : फाजिल्का में 30 प्रतिशत कपास इसलिए खराब हो गई कि खाद में मिलावट की गई थी। ऐसी बीमारी हो सकती है जो खराब खाद के कारण हुई हो। इसके बारे में मैं यू एन आई की न्यूज पढ़ देता हूं।

"Nearly 30 percent of the cotton crop in the Fazilka Sub-Division has been damaged because of spurious fertilizers and the loss is estimated to be about Rs. 16 crores."

यह हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी है, यू एन आई की न्यूज है। क्योंकि सवाल आया है कि अज्ञात बीमारी की बजह से नुकसान हुआ तो इसकी बात तो अलग है लेकिन खाद के अन्दर खराबी के कारण जो फसल खराब हुई है इसकी भी जांच आप कृषि विशेषज्ञों के द्वारा कराये कि खराब खाद डालने से क्या नुकसान कपास की फसल को हुआ है।

कपास के पौधों के ढेर को देर तक रख दिया जाय खेतों के अन्दर या किसान जो घर के अन्दर रखते हैं उससे भी एक बीमारी होती है जिसको पी वी डब्ल्यू कहते हैं। श्री एम आर बाजीकर, सीनियर मैनेजर, प्लानिंग एण्ड टेक्नीकल डेवलपमेंट, पेस्ट कंट्रोल इंडिया लिमिटेड ने कुछ सुझाव इसके बारे में दिए थे। उनका कहना है कि इसको अगर तुरन्त जला दिया जाय तो शायद इस बीमारी पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को बताया जाय और आवश्यक हो तो कानून भी बनाया जाय। हमारे देश में कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसका बहुत महत्व है। गरीब लोग पोलिस्टर बगैरह के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, ज्यादातर वे सूती कपड़े ही पहना करते हैं। अगर कपास का मूल्य बढ़ेगा तो कपड़े के मूल्य भी बढ़ेंगे जिसका इस देश के गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी कपास की पैदावार होती है लेकिन इस बार तमिलनाडु में भी कपास की पैदावार घट गई है क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ऐसी कारगर कार्यवाही करे जिससे कि जो भी फसल है, वह अज्ञात बीमारी या प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट न हो पाए। सरकार इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए और अभी तक सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर चुकी है—यह भी मैं जानना चाहूंगा।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, आप तो खुद किसान हैं और आपको इसके बारे में जानकारी है। पहली बात तो मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यह कोई अज्ञात बीमारी नहीं थी। बल्कि कीड़ों द्वारा नुकसान हुआ है। काटन बाल बोर्स होता है जो कपास के टिण्डर में सूराख करके उसको खराब कर देता हैं जिससे कपास का रंग भी खराब होता है और उसकी पैदावार भी घट जाती है। इसकी बजह से किसान को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। यह कीड़ा आम तौर से लगता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा इस कीड़े की रोकथाम की जाती है। इस बार बारिश लगातार होती रही और अगर बारिश बार-बार हो तो उससे केमिकल्स का स्प्रे घुल जाता है और उसका पूरा असर नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि बारिश ज्यादा होने से पत्तों का ज्यादा फैलाव हुआ कपास में और उसकी बजह से भी कीड़ों को ज्यादा बढ़ावा मिला। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की तहत 37 रु० 50 पैसे फी हैक्टेयर की सब्सीडी एरियल स्प्रेइंग के लिए दी जाती है जिसमें से आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती हैं और आधा पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह पैसा पहले ही अन्दाजे से दे दिया जाता है और यह पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी जरूरत हों मालूम हुई उसके मुताबिक एयरक्राफ्ट भी स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई किये गये। वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप एयरक्राफ्टस का इन्तजाम करती हैं—अपने एयरक्राफ्ट से या प्राइवेट एयरक्राफ्ट से वे स्प्रेइन्ग कराती है।

इस समस्या से अध्यक्ष महोदय, आप भी चिंतित थे, आपने स्टेट गवर्नमेंट से भी कहा था। वहां पर एक टीम भी यहां से गई और सर्वे हो रहा है लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। पंजाब गवर्नमेंट विचार कर रही है कि किसानों की इमदाद के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। शार्ट टर्म लोन्स को लांग टर्म लोन्स में तब्दील किया जा सकता है। उसके लिए बातचीत कर सकते हैं और उसमें जो सहायता दी जाती है उसमें दिक्कत नहीं है। अगर समय से मालूम होता कि इस बार इतने बड़े पैमाने पर कीड़े का हमला है तो शायद सेन्ट्रल गवर्नमेंट और ज्यादा इमदाद उसकी रोकथाम के लिए कर सकती थी, अपने एक्सपर्ट्स को भी भेज सकती थी।

अध्यक्ष महोदय : आप खुद दौरा लगाइये, फिर आपको पूरा पता लग सकेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर कहीं से यह रिपोर्ट आती है कि अंदाजन 15-20 फीसदी नुकसान हो गया है तो उसमें यह मानना पड़ेगा कि किसी-किसी किसान का सौ फीसदी नुकसान भी हुआ होगा, किसी गांव में भी सारा का सारा नुकसान हो गया होगा या किसी ब्लाक में भी सारा नुकसान हो गया हो।

अध्यक्ष महोदय : किसान सारा साल इसी पर निर्भर करते हैं। मैंने खुद वहां जाकर देखा है और आपको चिट्ठी भी लिखी है।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्टेट गवर्नमेंट से पूरी रिपोर्ट मिल जाने पर...

अध्यक्ष महोदय : जिस तरह से फ्लड्स और टाइकून बगैरह में कंम्पेसेशन दिया जाता है उसी तरह से अगर यहां पर भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पायेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : कंम्पेसेशन देने की अभी तक तो कोई स्कीम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से मालूम होने पर, पूरी रिपोर्ट आने के बाद विचार किया जा सकता है और हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर काल-एटेंशन एडमिट करके चर्चा करने का मौका दिया है। यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकार को अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं सरकार से पहली बात यह पूछना चाहता हूं कि क्या सेन्टर और स्टेट का आपस में कोई तालमेल भी है या नहीं ? यदि मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य के पहले और दूसरे वाक्य को पढ़ा जाए—वे कहते है कि कोई बीमारी नहीं है और कोई सूचना नहीं है और दूसरे में बीमारी बताना शुरू करते हैं। आपको याद होगा एक पिता अपनी

(श्री सूरज भान)

लड़की की सगाई करने के लिए बात करने गया। उसने पूछा कि लड़का कैसा है ? उसने कहा— लड़का बिल्कुल अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कभी-कभी जब वह दोस्तों में बैठ जाता है तो ताश खेल लेता है। जब ताश खेलता है तो कभी-कभी थोड़ी शराब भी पी लेता है। जब पी लेता है तो कभी और कुछ धन्धा भी कर लेता है। इस तरह वे आहिस्ता-आहिस्ता सारी बातें कहते गए। ऐसा ही एक उदाहरण आपने पेश किया है।

अखबार में छपा है कि 80 फीसदी नुकसान हुआ है। आपने माना है कि पंजाब में 15 से 20 प्रतिशत और हरियाणा में 20 से 25 प्रतिशत नुकसान हुआ है। हालांकि अखबार की रिपोर्ट ठीक नजर आती है, यदि आपकी रिपोर्ट को भी मान लिया जाए...

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं सौ फीसदी मानने को तैयार हूं।

श्री सूरज भान : राव साहब मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर टोटल क्राप का 15 फीसदी भी मान लिया जाए, तो कुछ किसानों का सौ फीसदी नुकसान हो गया होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल सही बात है।

श्री सूरज भान : टोटल का यदि 25 फीसदी हो सकता है और जिसका सौ फीसदी नुकसान हुआ होगा, उसके मन पर क्या बीत रही होगी आप जवाब दे रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई कम्पेंसेशन की स्कीम नहीं है। यदि अब तक नहीं है, तो अब कर लीजिए। राज्यों से तय कीजिए और आइंदा के लिए कर दीजिए। उनको सौ फीसदी कम्पेंसेशन मिलना चहिए। आपने माना है कि...

अध्यक्ष महोदय : सूरज भान जी आपने एक कहानीसुनी होगी। पहली दफा गंगानगर में गन्ना लगा। वहां कोई जैसलमेर साइड से तहशीलदार आ गया। किसान लेकर खेत में देखने के लिए गए, गिरदावरी चैक हो रही थी, किसी ने कहा कि इसमें बहुत खराबी हो गई है। उसने पूछा कि क्या खराबी हो गई है? कहा कि इसमें एक भी गुड की भेली नहीं लगी हुई है। उसने मान लिया कि बिल्कुल ठीक बात है।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसम्बर के आखिर तक पंजाब में छिड़काव का लक्ष्य एक लाख हैक्टेयर था, लेकिन सितम्बर 1983 के अंत तक 39 हजार हैक्टेयर पर छिड़काव हुआ। इसका मतलब यह है कि 61 हजार हैक्टेयर जमीन पर छिड़काव नहीं हुआ। इसी प्रकार हरियाणा में 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव का टारगेट था, लेकिन हुआ केवल 24 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में। इसमें भी 6 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? यह बात केवल पंजाब और हरियाणा को ही नहीं है, गुजरात में भी यही हालत है। मेरा निवेदन है कि आप खुद भी वहां जाकर निरीक्षण करें और साथ में एक्सपर्टस की टीम को भी साथ लेकर जायें। मैं आज तक आपको किसान समझता रहा हूं लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं, कि एक्सपर्टस की टीम को भी साथ ले जायें। आप हरियाणा के रहने वाले हैं। आपको पंजाब और हरियाणा की कोई भी जानकारी न हो, इससे ज्यादा और हैरानी की बात क्या हो सकती है।

आपने उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। उत्पादन बढ़ाने के साथ प्लांट प्रोटैक्शन का सवाल पैदा होता है, इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं? छिड़काव का काम तो आप से पूरा

हो नहीं पा रहा है। प्लांट प्रोटैक्शन कैसे करेंगे? जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उनकी क्वालिटी, कीमत, कम से कम अपने नियन्त्रण में ले लीजिए। कैसे उनके पास दवाई जाती है, कितने भाव पर जाती है। किस क्वालिटी की जाती है, सब स्टैण्डर्ड तो नहीं है। इन बातों को यदि आप अपने नियन्त्रण में लेलें, तब उनको कुछ लाभ हो सकता है।

फाजिल्का और अबोहर तहसीलों में कपास कम होने का एक कारण बीमारी हो सकती है, लेकिन एक दूसरा कारण वहां यह भी है कि वहां पानी का लेविल बढ़ गया है। यह साइंस का जमाना है, आप सायंसदानों को कन्सल्ट कर सकते है कि वहां से पानी का निकास कैसे किया जा सकता है। ताकि ये फसलें वहां आइंदा भी बोई जा सकें। इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये

आपने पैदावार बढ़ाने की बात कही है। पैदावार तब बढ़ेगी जब किसान को अच्छा दाम मिलेगा। सबसे पहले तो यह कोशिश की जाये कि उसको अच्छा दाम दे सकें, उसके बाद एक दुसरी बात भी है आपने मोटी कपास के भाव का काम तो ए.पी.सी. को दे रखा है लेकिन जो फाइन कपास पैदा होती है, लांग-स्टेपल, उसको टैक्सटाइल कमिश्नर को दिया हुआ है। ऐसा क्यो किया गया है? कपड़ा तो मोटी कपास का भी बनता है आप दोनों का काम ए. पी. सी. को क्यों नहीं देते? हालांकि इन्साफ तो ए.पी.सी. से भी नहीं मिल रहा है, लेकिन टैक्सटाइल कमिश्नर से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि कपास का पूरा काम ए.पी.सी. के सुपुर्द कीजिये ताकि किसान को सही दाम मिल सके।

आखिर में सबसे जरुरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपकी जानकारी अधूरी है, बेहतर होगा कि आप पूरी जानकारी हासिल करें, सैन्टर की टीम वहां भेजें और इस इशू पर फिर से यहां एक बार चर्चा हो जाय।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितनी मोटी-मोटी बातें उठाई गई हैं या आपने भी जो सवाल उठाये हैं उनका जितना जवाब मैं दे सकता था, दे चुका हूं। अभी तक आनरेबिल मेम्बर की समझ में यह बात नहीं आई है कि बीमारी और कीड़े में फर्क होता है...

श्री सूरजभान : आदमी को कीड़ा काट लें तो क्या वह बीमारी नहीं होगी?

राव बीरेन्द्र सिंह : आपको बाहर कुत्ता काट ले तो वह बीमारी होगी या कुत्ते का काटना होगा?

श्री सूरज भान : लाजमी तौर पर बीमारी होगी। डाक्टर से पूछेंगे तो बीमारी कहेगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : कीड़े का काटना या जानवर का काटना बीमारी नहीं है।

श्री सूरजभान : यह डेफिनेशन मुझे मालूम नहीं थी।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब मालूम हो जानी चाहिये।

हरिकेश बहादुर जी ने भी कहा कि कोई अज्ञात बीमारी लग गई है, जैसे कोई वायरस डिजीज हो या कोई नया बैक्टीरिया हो यह जो कीड़ा है इसकी जानकारी हमें है। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे काफी नुकशान हुआ है। पहले तो यह रिपोर्टस आती रहीं और मुझे पंजाब और हरियाणा के फार्म से भी मिलते रहे जो कहते थे कि देखने से यह मालूम होता था कि कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है लेकिन

(श्री राव बीरेन्द्र सिंह)

बाद में कीड़ा लगा और उससे यह नुकसान हुआ।

दूसरी बात आपने भी दोहराई है और हरिकेश जी ने भी बार-बार कहा और जिसका जवाब भी मैंने नहीं दिया, इसलिये कि मैं समझता था कि इस मामूली सी बात को आप समझते होंगे कि खाद अगर सब-स्टैण्डर्ड हो, नाकिस हो, तो उससे कीड़े पैदा नहीं होते हैं, बाल-वार्म पैदा नहीं होता है। खाद की वजह से नुकसान नहीं हुआ है। अगर खाद सब स्टैंडर्ड है तो वह दूसरा विषय है और उसके लिये उपाय हो रहे हैं क्वालिटी कन्ट्रोल करने जा रहे हैं, रीजनल लैबोरेट्रीज जगह जगह पर चलाने की स्कीम है, सेम्पल्ज ज्यादा से ज्यादा लिये जा सकें, स्टेट गवर्नमेन्टस ने जो लेबोरेट्रीज बनाई हैं उनकी क्षमता बढ़े, ज्यादा सेम्पल्ज उठाये जा सकें टेस्ट भी जल्द से जल्द किये जा सकें, सजायें भी पूरा दी जांय।

श्री सूरज भान : एक्सपर्टस की राय भी लीजिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे जो एक्सपर्टस की राय मिली है वही कह रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आम लोगों के सामने कोई भी बात कहते हुए काफी घबराता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह कौन मानेगा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो हम पहली दफा सुन रहे हैं कि राव साहब घबराते हैं।

श्री सूरज भान : कम्पेसेशन और पानी के लेबिल के बारे में नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : कम्पेसेशन के बारे में बता दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : कम्पेसेशन की बात स्पीकर, साहब ने भी कही और आप ने भी कही। इसके लिए अभी तक जो हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं और जिन चीजों के लिए सहायता दी जाती है। वह आपको मालूम है। दूसरी फसल किसान अच्छी पैदा कर सके, उसके लिए कर्जे की सुविधा हो जाए। इसके अलावा जो शोर्ट-टर्म लोन है। उसको लांग-टर्म में लोन में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह की उन की सहायता हो जाए और खाद वगैरह जो हैं या जो दूसरी चीजें हैं वे छोटे किसानों को सस्ते रेट पर दे दी जाए। अगर सूखे के कारण फसल बिल्कुल बरबाद हो जाए, तो उसके लिए सहायता मिलती है और लोगों को काम दिलाने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ का बन्दोबस्त किया जाता है इसके अलावा फ्लड्स आ जाए, तो 75 प्रतिशत की सहायता बहुत सी मदों में भारत से स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। और उसके लिए कुछ स्कीमें हैं लेकिन इसमें क्या कुछ हो सकता है, वह पूरी रिपोर्ट पंजाब सरकार से आने के बाद और हमारे अफसरों के जरिये से जानकारी हासिल करने के बाद ही, कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको काआर्डीनेट करें।

श्री मोतीभाई आर. चौधरी : (मेहसाना) दवाइयों में मिलावट भी होती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी, हां वह भी होती है

अध्यक्ष महोदय : श्री उत्तम राठौर।

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : Mr. Speaker. Sir, it is an irony of fate that in a country where 70 per cent of the population lives on agriculture, where the Minister

in charge of Agriculture at the Centre happens to be a friend of farmer, who has achieved a great name in his State when he was the Chief Minister, in spite of his being in charge of it, the Agriculture Department has been taking its activities in a very casual manner. You rightly pointed out the discrepancies that have occurred in the first and second sentence. Mr. Harikesh Bahadur also pointed out the same, and let me tell you here that they say that they have not received any report. In the second paragraph they have said that the damage in Punjab is 15 to 20 per cent and in Haryana it is 20 to 25 per cent. This is in paragraph 2. When they give information about their spraying and other activities, they say that in Punjab the target was 1 lakh hactares for 1983 while they could complete only 39,000 hectares of spraying, while in Haryana it was only 30,000 hectares where they could complete, 25,000 hectares of spraying. In spite of that, if you compare the damage, you will see that the damage is more in Haryana. From this fact itself it will be evident that the cotton crop in Punjab and Haryana has been greatly damaged. I come from an area which is mainly a cotton producing area, namely, Maharashtra. Our neighbouring States like Gujarat are the main producers of cotton. We produce more than 50 per cent of cotton from these two States. Then Andhra is there, Rajasthan is there, Tamil Nadu is there, Karnatka is there and when I enquired from every State. everybody said that due to heavy rains this year no proper spraying could be done and the cotton crop has been badly damaged. We are told that the State Government gets a crop report every week from their collectors or from their respective departments. The State is also expected to send their reports to the Central Government about the crop condition If this not a fact how the hon. Minister would have made a statement that 'this year the crop condition is good and we are expecting a better harvest'? I want to know that. He must have had some source of information from which he could deduce that this year the crops are going to be good and that is why he could make a statement. How is that? A man like Rao Birendra Singh failed to enquire about the cotton crop which is the only cash crop for most of the cultivators in this country. Only 25 per cent of cotton is grown under irrigation and the rest of the 75 per cent crop depends on the vagaries of nature. I would like to point out certain things.

13.00 hrs.

Rao Birendra Singh was kind enough to tell us which are the things that they treat as natural calamities and in which they try to help. We have gone much ahead in Maharashtra. We face floods and heavy or excessive rains. There the Government has not only helped the people whose crops have been damaged by floods but also people whose crops have been damaged by excessive rains.

Go to Andhra Pradesh from where Shri Vijaya Bhaskara Reddy comes. When there was cyclone. he went to the people and helped them by giving money so that farmers and cultivators may be able to face the calamity and be in a position to take up harvest next year.

Why should the Government of India not help the States by enlisting this particular calamity as a natural calamity and give them help. Do not expect the State Governments to come to you. You are supposed to be in a position to know everything. You are their big brother. But as a big brother you also owe some responsibility. You should visualise. You should forecast things and try to enlist that in the notural calamity and try to help them. You rightly pointed out and fortunately for us you are also a farmer. The crops in Haryana and Punjab have miserably failed and the same is the case in Maharashtra, Gujarat, Karnataka, etc. I would like to request the hon. Minister to do away with the interest part of the loan that has been extended to the cultivators by co-operative and other financial institutions for the period from the day of sowing to fifteen future months, when he will be in a position to repay you in case he has a good produce. If he does not pay, we can penalise him. Give him that satisfaction. You can definitely waive that interest part of it and save him.

(Shri Uttam Rathod)

We have been talking a lot about the crop Insurance Scheme. At least that should have been brought much earlier. We have taken Bunding Soil Conservation and other schemes. But this Crop Insurance Scheme has not been introduced which is of a vital necessity for the cultivator. When you are not doing. why do you not try to give relief through waiving interest ? Secondly, next year is going to be difficult. Minister has rightly stated that it can be treated as mid term loan. In the mid term loan only recovery will be stayed. But what about the interest ? Interest will have to be waived. The cultivator is not in a position to repay you back. This country survives on the sweat and labour that has been put in by the cultivator. Are we going to give him that treatment ? You will be shocked to know when Shri Jadeja, the hon. Member from Gujarat asked a question whether Government has received any request from the cotton growers to increase the price, the Government said that they had not received and in the last stage they said that there has been some such thing. I do not know why do you take things so lightly. Cotton growers have been asking for parity—the price that has been paid to the cotton growers and that they have to pay for finished goods. Why cannot you do it ? What is wrong ? Same is the case with bajra, jawar and all the agricultural produce.

In Maharashtra, only last week, Shri Sharad Joshi went to Pandharpur for this purpose.

Those who do not plead the cause of agriculturists they are against the Indian people.

I wanted to say it is high time for the Government to take up in right earnest the suggestions that have been given by Shri Sharad Joshi and other cultivators. They must take cognisance of it seriously and not casually.

At this stage, I would only request the hon. Minister to please treat excessive rains or dry spell as a natural calamit. to please give them all the benefit that you give in the case of other natural calamities, to please help them because they are 70 per cent of your population, because they are most illiterate and they cannot approach big people, please give them all help so that they can sustain and live longer to serve you.

RAO BIRENDRA SINGH : The hon. Member has raised some points. I am sorry to say that perhaps I have not been able to explain fully.

As regards the question of estimates with regard to losses, as stated by my hon. friend, there can be various sources with regard to estimates. He could have his own information. I may collect information from various other quarters. But here we have to depend upon the reports that we receive from the State Governments which are considered authentic. But these can always be checked and we shall check them.

The hon. Member asked : How is it that we come to know in advance and predict production with regard to certain crops ? I have stated again and again that we expect a very good rabi crop. But if there is no electricity available or some other disease overtakes the good crop, our estimate will certainly fail. The same thing happened in this case. The crops were good. But on account of the attack by the pest, the cotton crop has suffered and, I believe, since you have also expressed your view, the extent of less is very great.

Compensation can only be provided through crop insurance. But cotton crop is not covered by crop insurance in any State. We have been proposing to the States that they should take advantage of our policy with regard to crop insurance.

Another point made was with regard to the area sprayed by air. Aerial spraying does not cover the entire area that is treated. There is a large area covered by handspraying also. It has already been stated that the area covered by aerial spraying this year has been less than what was planned for on account of certain factors, namely, intermittent rains, bad weather, not allowing the aircraft to operate properly. It is on that account that

the State Governments perhaps could not achive their targets.

With regard to loans and interest, in case of heavy losses, the State Governments do remit interest also. They also remit the loan. Recoveries are also postponed. But the proposal in that regard should come from the State Government. They should themselves consider the matter before the Central Government can say as to what assistance can be provieded to the State Governments.

As I stated, it is not possible to commit the Central Government for compensating the losses on crops form such calamities because it may be such a huge burden that the Central Government will not be able to bear. Recently, the apple crop in Himachal Pardesh was badly affected by scab disease, In drought also, large areas are completely ruined and the farmers do not get anything out of their investment on cultivation. But any special assistance that can be given to the farmers will be considered after the State Government has send us their proposals. As you know, they have already approached NABARD. They have taken some decision about the conversion of short-term loans into long-term loans. The State Government can also waive the interest if they like. If their resources do not allow, they can always approach the Central Government in this regard.

SHRI UTTAM RATHOD : What about parity between finished and raw goods ?

RAO BIRENDRA SINGH : As you know, very well, we have accepted the principle of parity.

The terms of reference of the Agricultural Prices Commission were revised as soon as this Government was formed in 1980. The principle has been accepted. But I agree that it has not been able to achieve this parity completely so far. The farmer is not able to get the remunerative price for agricultural produce that he gets after paying for the inputs repuired.

SHRI BHIKU RAM JAIN : The debate, the way it has taken place as a result of the Call Attention, is almost like a political debate. Somebody is alleging that the damage is to the extent of 80% while the Government is saying it is about 20-25% and they do not remain in knowledge because the States have not provided any information. I only wish to say that cotton is a very important commercial crop and the cultivation of this crop is in the interest of the cultivator and the nation. It plays a key role in the political, social and economic spheres of not only the cultivator but also the nation as a whole. I say so because almost over 8 million hectares of land is under cotton cultivation. India has the largest area under cotton cultivation throughout the world and, from the point of view of production, India probably ranks fourth in the whole world. We have been importing and exporting cotton and we have a very large number of textile mills which depend upon cotton and on the supply of cotton I, therefore, say from the economic point of view that apart from the cotton produced in this country for the economy of the cultivator in this country it has an economic effect on the other aspects of the national economy and, therefore, I wanted to know whether we have laid the cotton production at the mercy of nature Are we to depend on rainfall? There was a cyclone in Gujarat last year. What has the Government done in regard to the protection of this industry which is not only an agricultural industry but is also a cotton textile industry. It has a very large stake in this country providing employment to thousands and thousands of people. I therefore, request the Hon. Minister to advise whether the Government at the centre and in the States, have taken any steps to protect this crop which has a repercussion on the national economy, on the State economy as well as on the individual economy of the country.

RAO BIRENDRA SINGH : The Centrally sponsored scheme for assistance to farmers in the matter of cotton cultivation has been mentioned in the Statement. I agree that cotton is a very important crop in the country. But the purchases and the price support as declared by the Government is provided by the Cotton Corporation of India which is under the Ministry of Commerce. That is why, the Ministry of Agriculture cannot say much about the prices available

(Rao Birendra Singh)

to the farmers. But we will try to fix remunerative prices from time to time and there is also a differential between the common variety of cotton and the superior varieties of cotton but that also has to be decided by the Textile Commissioner, as was mentioned by Hon. Members.

I only assure, and through you, the whole House that the Government is fully aware of the importance of cotton crop. The claims of cotton growers in this country made through the Government, whether through the Central Government or through the State Government, fully deserve all our sympathy and assistance in times of calamities.

SHRI BHIKU RAM JAIN : I wanted to know about the protection provided by the Government for cotton production in areas where there is no rainfall and where there is heavy rainfall and where there are cyclones. Are they to depend on nature or is there something which the Government can do to solve the problem of crop failure on account of the vagaries of weather.

RAO BIRENDRA SINGH : Cotton crop is one of the important crops like foodgrains, sugar cane or any other agricultural crop in the country and it gets the same facilities on par with other crops. Water also is given, canal water, tubewell water, for cotton cultivation in some places on a priority basis. There are certain schemes of the Central Government which have been mentioned in the statement for production of good cotton seed. Research is also being conducted and large sums of money are spent on it. Processing units are also set up to help cotton-growers and textile mills. There are cooperatives also which are in the field. There are spinning mills; a large number of them are coming up. Ginning mills are also being set up by private parties, as also by farmers through cooperatives. All this is to help the farmers.

SHRI BHIKU RAM JAIN: This is after the Produce is ready. What I am talking about is at the time of Production. protection to the farmer when he has not yet produced. After production, of course, there are mills, ginning mills, textile mills and so on.

RAO BIRENDRA SINGH : Subsidy is allowed for spraying operations to save the crop. Good seed is being supplied and it is being multiplied. Better and better seeds are also evolved for the farmers. All this takes place. Water is also ensured for cotton crop. Electricity is also being made available to the farmers for growing cotton. Diesel is also made available to the farmers for growing cotton The chemicals that are used for plant protection are also being properly monitored with regard to quality and other things. We try to keep a check on all the needs of the farmer so that he does not suffer because of lack of certain inputs that he needs.

MR. SPEAKER : Mr. Shejwalkar is not present. The House stands adjourned for lunch till 14.20 hrs.

13.17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till twenty minutes past Fourteen of the Clock

The House re-assembled after Lunch at Twenty Four minutes past Fourteen of the Clock

(MR. R.S. SPARROW *in the Chair*)

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : With your permission.

Sir, I rise to announce that Government Business in this House for 21st and 22nd November, 1983, will consist of :

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Ordinance, 1983 and consideration and passing of the illegal Migrants (Determination by Tribunals) Bill, 1983.